12.00 Noon

माननीय सदस्या ने अपने विचार रखे, वे बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं। संथाली भाषा में अनेक तरह की समृद्ध रचनाएं हैं, जिनके बारे में बाहर लोग नही जानते और उनका अनुवाद भी बाहर की भाषाओं में बहुत कम हुआ है। उन्होंने जिस पंडित रघुनाथ मुर्मू का उल्लेख अपनी तक़रीर में किया, वे बड़े साहित्यकार, बड़े मूर्धन्य और एक किस्म से उनके बीच बड़े पूज्य हैं। खास तौर से संथाली भाषा में उनकी संस्कृति, कविताएं, उनका रहन-सहन, उनके घरों के आर्ट आदि बड़ी समृद्ध परम्परा है। इसी तरह अन्य आदिवासी इलाकों में भी चाहे वे 'हो' हों, 'मुंडारी' हों, 'संथाली' हों, उनके यहां भी अलग-अलग बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके काफी सारे युवा लड़के पूरे देश में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और इस देश में आदिवासियों की बड़ी संख्या में तादाद है। निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों से उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question Hour, Question No. 196.

Surge in prices of edible oil

*196. SHRI KUMAR KETKAR: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a huge gap between demand and supply of edible oil in the country due to the failure of soyabean crop to a very large extent in Maharashtra; and

(b) if so, the steps taken by Government to arrest the surge in prices of edible oil in the open market due to this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO): (a) and (b) A Statement is laid on the Table.

Statement

(a) and (b) The domestic production of edible oils is not adequate to meet their demand in the country. The gap between demand and production of edible oils is met through imports.

The production of Soyabean in Maharashtra for 2019-20 is expected to be 42.08 Lakh MT as compared to 45.48 Lakh MT m 2018-19. However, the expected production of 42.08 LMT of Soyabean in 2019-20, in Maharashtra, is more than the last five year average production of 34.77 LMT. In case of any decline in the domestic production, the gap between demand and availability is met through import of edible oils.

The wholesale prices of major edible oils varied from (-) 0.68% to (+) 6.88% while the retail prices varied from 0.17% to 7.05% over the past one year. However, during the period, the wholesale and retail price of soyabean oil has increased only by 3.13% and 2.79% respectively.

SHRI KUMAR KETKAR: Sir, it is necessary to recognize that we are an edible oil guzzling country. We import something like Rs.77,000 crore worth of edible oil and the imported edible oil is often genetically modified (GM). Our country bans genetically modified products.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question briefly.

SHRI KUMAR KETKAR: Why should not the import duty be extended so that the local producers and local refiners are benefited?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि इस साल सोयाबीन की फसल में भारी मात्रा में कमी आई है। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूं कि इस साल लेट बारिश और बेमौसम ज्यादा बारिश होने के कारण कमी आई है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि आयात शुल्क क्यों नही बढ़ाते हैं? उपसभापति महोदय, हम 60% तेल बाहर से लाते हैं और 40% ही घरेलू उत्पाद होता है। सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है। अगर आप पिछले पांच साल के आंकड़े देखेंगे, तो 34.77 लाख टन का उत्पादन हुआ था, इस साल वह 42.8 लाख टन हुआ है। अगर तीन वर्ष के आंकड़े देखें, तो 43.72 लाख टन का उत्पादन हुआ और इस साल 42.8 लाख टन का उत्पादन हुआ है। केवल 1.4 लाख टन का अंतर है। महोदय, हम 60% तेल बाहर से लाते हैं, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बार-बार कोशिश जारी रखती है।

श्री उपसभापति: केतकर जी, अपना दूसरा सप्लीमेंटरी पूछिए।

SHRI KUMAR KETKAR: Sir, is it not possible to reduce import by increasing the import duty because edible oil producers and groundnut and other edible oil producers and farmers are suffering? I think the price of imported oil, if it is raised, will help the farmers as well as the refiners.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, सरकार बार-बार यह कोशिश करती है कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा तिलहन के तेल का उत्पादन किया जाए। सरकार ने तिलहन के बढ़ते दाम को रोकने के लिए जो कुछ उपाय किए हैं, उसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन किया है। सर, जो रिज़-फरो कलस्टर पद्धति है, जिसमें demonstration करके ज्यादा उत्पाद कैसे होगा, इसका भी इलाज सरकार करती है। अनाज में दलहन, तिलहन की फसल बीच में रिज़-फरो क्लस्टर में डालनी चाहिए, इसका भी सरकार बार-बार प्रयास करती है। सर, इसका मतलब यह है कि इस देश में जब तक तेल का उत्पादन नही बढ़ेगा, तब तक बाहर से लाना ही एक रास्ता है।

श्री पी.एल. पुनिया: धन्यवाद, उपसभापति जी। Edible Oil की कमी को दूर करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया से crude palm oil इम्पोर्ट किया जाता है और वहां पर भी लगभग 26% crude oil prices में बढ़ोतरी हुई है। यहां हिंदुस्तान में सोयाबीन की फसल खराब हुई है और रबी की बुआई में भी सुस्ती चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य तेलों की कमी को दूर करने और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या आपने कोई रोडमैप तैयार किया है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, मैंने जवाब में बताया है कि सरकार खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। मैंने बोला है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए रिज़-फरो क्लस्टर का एक demonstration करके इसका उत्पादन कैसे बढ़े, सरकार इसकी बार-बार कोशिश करती है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो 3,399 रुपए उसका समर्थन मूल्य था, वह इस बार बढ़कर 3,710 रुपए हो गया है। उसके समर्थन मूल्य में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि तेल की कीमतों में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 0.68 से लेकर 6.88 तक का variation आया है और इसकी कीमतें ज्यादा नही बढ़ी हैं। जहां तक कीमतों का सवाल है, जब तक इसका घरेलू उत्पाद नही बढ़ेगा, तब तक वे ज्यादा नही बढ़ेंगी।

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Sir, as we know, the prices of all essential food items are rising, be it onion, tomato or edible oil. Onion prices have tripled in the last two months at most of the places. I would like to ask of the hon. Minister: What is the Government doing to help the common women and men of this country in a situation where buying supplies for daily food is becoming a struggle?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to edible oil.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई संदेह नही हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि इस बार बरसात देर से हुई और ज्यादा दिन तक बारिश चलने के कारण प्याज क्षतिग्रस्त हुआ। प्याज ज्यादातर महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है। महोदय, गवर्नमेंट के पास buffer stock था, उसके ज़रिए भी प्याज दिया गया, लेकिन प्याज के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसमें कमी आयी। सरकार ने

एमएमटीसी की तरफ से बाहर के देश से कांदा मंगवाया है और 20 जनवरी तक वह कांदा आ जाएगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह कोई जवाब नही है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I would like to ask this from the hon. Minister. There are crops like palm oil which can actually give a substantially large yield compared to other crops. Does the Ministry propose to enhance or give incentives for increasing domestic production of palm oil so that we can reduce import of palm oil from Malaysia and elsewhere in the world, and give benefits to the farmers?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सरकार का बार-बार प्रयास रहा है कि घरेलू उत्पादन कैसे बढ़े। इसके लिए सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" का कार्यान्वयन किया है, उसमें कई योजनाएं, जैसे sprinkler आदि कई चीज़ों का प्रावधान किया है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। जब तक यह घरेलू उत्पादन नही बढ़ेगा, तव तक आयात करना जरूरी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 197.

किसानों का कर्ज माफ करना

*197. **श्री प्रभात झा** : क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों की वर्तमान सरकारों द्वारा किसानों के सम्पूर्ण कर्ज को माफ करने की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तीनों राज्यों द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप किसानों के सम्पूर्ण कर्ज को माफ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नही

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की वर्तमान राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई कर्ज माफी योजनाओं का संक्षिप्त सार और कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है: